

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3338

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

**सड़क ठेकेदारों द्वारा कम बोली लगाना**

†3338. श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सड़क परियोजनाओं के लिए सड़क ठेकेदार निविदा लागत से काफी कम बोली लगा रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 2014 से अब तक सरकार द्वारा आवंटित परियोजनाओं का निविदा लागत, ठेकेदारों द्वारा लगाई गई बोलियों सहित वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014 से अब तक निविदा लागत तथा लगाई गई बोली के बीच का अंतर (प्रतिशत में) कितना है;

(ग) क्या ठेकेदारों द्वारा लगाई गई अत्यंत कम बोलियों के कारण सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता और उनका समय पर पूरा होने में बाधा आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी सड़क परियोजनाओं के लिए बोली लगाने हेतु अर्हता मानदंडों में ढील दी गई है और पुराने और नए मानदंड क्या हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने अत्यंत कम निविदा बोली के कारण घोषित किसी निविदा को रद्द किया है और यदि हां, तो 2014 से अब तक तत्संबंधी परियोजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार निर्धारित प्रापण दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना कार्यों के कार्यान्वयन के लिए संविदाकारों को नियुक्त करती है। कुछ मामलों में, निविदा में निर्धारित अनुमानित परियोजना लागत से काफी कम दरों पर बोलियां प्राप्त हुई हैं, जिसका मुख्य कारण प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थितियां और बोलीदाताओं द्वारा अपनाई गई आक्रामक बोली लगाने की कार्यनीतियां हैं।

सरकार के हितों की रक्षा करने और गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निविदा दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें अतिरिक्त कार्य निष्पादन सुरक्षा की आवश्यकता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, सभी कार्य निर्धारित प्रासंगिक

संहिता/नियमावली के अनुसार ही किए जाते हैं। स्वतंत्र इंजीनियर/प्राधिकरण इंजीनियर और नियमित फील्ड निरीक्षण निर्माण के हर चरण में पर्यवेक्षण और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कुछ परियोजनाओं में स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षा भी की जाती है।

तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

चल रहे कार्यों का औसत निविदा छूट राज्यों में 11% से 34% तक भिन्न होता है। परियोजना-वार और वर्ष-वार निविदा लागत और बोली लागत के बीच अंतर का डेटा बहुत अधिक है और इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

(ग) यह अनुमान लगाना संभव नहीं हो सकता है कि कम बोलियों के कारण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। आम तौर पर, कार्यों को निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। खराब गुणवत्ता के उदाहरण छूट के बिना वाली बोलियों में भी देखे गए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कार्य की गुणवत्ता मुख्य रूप से कच्चे माल की गुणवत्ता, उपकरणों की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण का स्तर, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और साइट पर श्रमिकों / इंजीनियरों के अनुभव के आधार पर प्रभावित होती है।

(घ) 2019 में, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए संविदाकारों/रियायतग्राहियों के लिए योग्यता मानदंडों में छूट दी गई थी। तथापि, 2025 में, आक्रामक बोली के कारण निर्माण समय-सीमा और गुणवत्ता से संबंधित संभावित समस्याओं को रोकने के लिए, सरकार ने अब हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएम) और इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए बोली लगाने हेतु योग्यता मानदंडों पर सख्ती की। इन संशोधनों में अन्य बातों के अलावा बोलीदाताओं के लिए कम वित्तीय और तकनीकी आवश्यकताओं को बढ़ाना, उप-अनुबंध अनुभव पर अधिक जांच प्रारंभ करना और राजमार्गों तथा मुख्य क्षेत्र की परिभाषाओं में संशोधन करना शामिल है। इसके अलावा, अतिरिक्त कार्य निष्पादन बैंक गारंटी का प्रावधान कड़ा कर दिया गया है।

(ङ) निविदाओं को आम तौर पर निविदा मूल्यांकन समिति की सिफारिश के अनुसार दिशानिर्देशों और सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के अनुरूप प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) में निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है।

\*\*\*\*\*